

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3903
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27 अग्रहायण, 1946 (शक)

व्यक्तिगत डेटा की चोरी

3903. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार व्यक्तिगत डेटा को चोरी की रोकने में पूरी तरह से विफल रही है जिसके कारण साइबर अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो व्यक्तिगत डेटा की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ग) क्या सरकार ने व्यक्तिगत डेटा की जानकारी/लीकेज के स्रोतों की पहचान की है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

- (क) से (ग):
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट अपने उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। सरकार विभिन्न साइबर खतरों और चुनौतियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। देश की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सक्षम करने के लिए सरकार ने कई प्रमुख पहलों की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 के प्रावधानों के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
 - सर्ट-इन ने अप्रैल 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 की उपधारा (6) के अंतर्गत सुरक्षित एवं विश्वसनीय इंटरनेट के लिए सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रिया, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित साइबर सुरक्षा निर्देश जारी किए। साइबर सुरक्षा घटनाओं को देखते हुए, सर्ट-इन संबंधित संगठनों को उपचारात्मक उपाय सुझाता है।
 - सर्ट-इन कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/भेद्यताओं और प्रतिउपायों के संबंध में निरंतर अलर्ट और सलाह जारी करता है।
 - सर्ट-इन ने विभिन्न मंत्रालयों को एक परामर्श जारी किया है जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना सहित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा या सूचना का प्रसंस्करण करने वाली सभी संस्थाओं द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों की रूपरेखा बताई गई है।
 - साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है और दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का

- पतालगानेमेंमददकरताहैऔरउन्हेंहटानेकेलिएनिःशुल्कउपकरणप्रदानकरताहैऔरनागरिकोंऔरसंगठनोंकेलिएसाइबरसुरक्षायुक्तियाँऔरसर्वोत्तमअभ्यासभीप्रदानकरताहै।
- vi. सर्ट-इननेसाइबरहमलोंऔरसाइबरआतंकवादकामुकाबलाकरनेकेलिएएकसाइबरसंकटप्रबंधनयोजनातैयारकीहैजिसेकेंद्रसरकारकेसभीमंत्रालयों/विभागों, राज्यसरकारोंऔरउनकेसंगठनोंतथामहत्वपूर्णक्षेत्रोंद्वाराकार्यान्वितकियाजाएगा।
- vii. भारतीयविशिष्टपहचानप्राधिकरण (यूआईडीएआई) नेआधारसंख्याधारकोंकेव्यक्तिगतडेटाकीसुरक्षाकेलिएव्यापकउपायकिएहैं। इसनेकेंद्रीयपहचानडेटारिपॉजिटरी (सीआईडीआर) डेटाबेसकीसुरक्षाकेलिएगहनसुरक्षाअवधारणाकेसाथबहु-स्तरीयसुरक्षाबुनियादीढांचेकोलागूकियाहैऔर यूआईडीएआईसिस्टमकीसुरक्षाकेलिएलगातारइसकीसमीक्षा/ऑडिटकरताहै। इसकेअलावा, सीआईडीआरकोएकसंरक्षितप्रणालीकेरूपमेंघोषितकियागयाहैऔरराष्ट्रीयमहत्वपूर्णसूचनाअवसंरचनासंरक्षणकेंद्रअपनीसाइबरसुरक्षास्थितिकोबनाएरखनेकेलिएनिरंतरआधारपरसुरक्षाइनपुटप्रदानकरताहै। यूआईडीएआईट्रांसमिशनऔरस्टोरेजमेंडेटाकीसुरक्षाकेलिएउन्नतएन्क्रिप्शनतकनीकोंकाउपयोगकरताहै।
- viii. सर्ट-इनद्वाराकार्यान्वितराष्ट्रीयसाइबरसमन्वयकेंद्र (एनसीसीसी) देशमेंसाइबरस्पेसकोस्कैनकरनेऔरसाइबरसुरक्षाखतरोंकापतालगानेकेलिएनियंत्रणकक्षकेरूपमेंकार्यकरताहै। एनसीसीसीसाइबरसुरक्षाखतरोंकोकमकरनेकेलिएकार्रवाईकरनेकेलिएसाइबरस्पेसमेंडेटासाझाकरकेविभिन्नएजेंसियोंकेबीचसमन्वयकीसुविधाप्रदानकरताहै।
- ix. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने भेद्यताओं को दूर करने और वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्ट-इन-पैनल वाली एजेंसियों के माध्यम से सरकारी वेबसाइटों, एप्लिकेशन्स और होस्टिंग बुनियादी ढांचे की आवधिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दी है।
- x. सर्ट-इन नेसितंबर 2023 मेंसुरक्षितएप्लिकेशनडिजाइन, विकासऔरकार्यान्वयनऔरसंचालनकेलिएदिशानिर्देशजारीकिए। सर्ट-इन नेअक्टूबर 2024 मेंसंस्थाओं, विशेषरूपसेसार्वजनिकक्षेत्र, सरकार, आवश्यकसेवाओं, सॉफ्टवेयरनिर्यातऔरसॉफ्टवेयरसेवाउद्योगमेंशामिलसंगठनोंकेलिएसॉफ्टवेयरबिलऑफमैटेरियल्स (एसबीओएम) दिशानिर्देशभीजारीकिएहैंताकिसंगठनोंकोयहजाननेमेंमददमिलसकेकिउनकेसॉफ्टवेयरया परिसंपत्तियोंमेंकौनसेघटकहैंजिससेभेद्यताओं कीपहचानकरनाऔरउन्हेंठीककरनाआसानहोजाताहै।
- xi. सर्ट-इन नेसूचनासुरक्षासर्वोत्तमप्रथाओंकेकार्यान्वयनकासमर्थनऔरलेखापरीक्षाकरनेकेलिए 155 सुरक्षालेखापरीक्षासंगठनोंकोसूचीबद्धकियाहै।
- xii. यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिअधिकृतभुगतानप्रणालीऑपरेटरों (पीएसओ) द्वाराभुगतानप्रणालीकोसुरक्षित, सुदृढ़औरकुशलतरीकेसेसंचालितकरनेकेलिएप्रौद्योगिकीकाउपयोगकियाजाए, भारतीयरिजर्व बैंक (आरबीआई) नेसभीपीएसओकोनिर्देशदियाकिवेअपनेभुगतानप्रणालीकावार्षिकआधारपरसर्ट-इनकेसूचीबद्धलेखापरीक्षकोंसेऑडिटकराएंऔरअपनेसंबंधितवित्तीयवर्षकीसमाप्तिकेदोमहीनेकेभीतरआरबीआईकोरिपोर्टप्रस्तुतकरें।
- xiii. डेटासुरक्षासुनिश्चितकरनेकेलिए, सूचनाप्रौद्योगिकी (उचितसुरक्षाअभ्यासऔरप्रक्रियाएँतथासंवेदनशीलव्यक्तिगतडेटायासूचना) नियम, 2011 ('एसपीडीआईनियम') संवेदनशीलव्यक्तिगतडेटायासूचनाकोसंभालनेवालेअनुपालनकरनेवालेनिकायकॉर्पोरेटयाउसकीओरसेकिसीभीव्यक्तिकेलिएउचितसुरक्षाअभ्यासऔरप्रक्रियाएँअनिवार्यकरताहै। निकायकॉर्पोरेटयाउसकीओरसेकिसीभीव्यक्तिकोऐसीजानकारीएकत्रकरनेसेपहलेउपयोगकेवैधउद्देश्यकेबारेमेंऐसीजानकारीकेप्रदातासेलिखितसहमतिप्राप्तकरनीहोगी।

- xiv. इसके अलावा, व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका डेटा केवल उनकी सहमति से ही साझा किया जाए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) लागू किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम का उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ताओं सहित व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है। डीपीडीपी अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू किया जाना चाहिए और कि सी भी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
